क्रेडिट स्कोर जानने के नाम पर ९० हजार रुपयेकी आनलाइन ठगी

जबलपुर, (एजेंसी)। कोतवाली थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। उपरैनगंज, दीक्षितपुरा निवासी ३२ वर्षीय आशीष विश्वकर्मा बैग बनाने और बेचने का काम करता है। आशीष के मुताबिक, २८ सितंबर की शाम उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने क्रेडिट स्कोर जानने के लिए नंबर-१ दबाने को कहा। उसके ऐसा करते ही मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल चालू करने के बाद अपडेट होने लगा और इसी दौरान उसके पंजाब नेशनल बैंक खाते से गूगल पे व फोन पे के माध्यम से पांच बार में अलग-अलग खातों में कुल ९० हजार रुपये ट्रांसफर हो गए। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा ३१८(४) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गिरवी रखे सोने की सस्ती नीलामी का झांसा देकर ३०.९५ लाख की धोखाधड़ी

लार्डगंज थाना क्षेत्र में फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से गिरवी रखे सोने को कम कीमत पर नीलामी में दिलाने का लालच देकर ३० लाख ९५ हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

हाउसिंग कॉलोनी, स्टेशन रोड कांचघर निवासी ३५ वर्षीय सुनील गुप्ता रेलवे में ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि २५ सितंबर को श्याम गुप्ता और निखिल विश्वकर्मा उन्हें तथा उनके दोस्त आदित्य देशमुख को लेबर चौक, यादव कॉलोनी स्थित फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ले गए। वहां मैनेजर सुरेंद्र सिंह पटेल और कैशियर दिव्या चौरसिया सहित अन्य लोगों ने हितग्राहियों द्वारा गिरवी रखे सोने को नीलामी में कम कीमत पर दिलाने का लालच दिया। शिकायत के अनुसार, सुनील गुप्ता से ऑनलाइन १० लाख ४० हजार रुपये और नकद १२ लाख ५ हजार रुपये, कुल २२ लाख ४५ हजार रुपये लिए गए। वहीं उनके दोस्त आदित्य देशमुख से भी ८ लाख ५० हजार रुपये लिए गए। रकम वापस मांगने पर रुपये नहीं लौटाए गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुरेंद्र सिंह पटेल, दिव्या चौरसिया, श्याम गुप्ता और निखिल विश्वकर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा ३१८(४) और ३(५) के तहत मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

देवी दर्शन के बाद घर लौट रहे युवकोंपर चाकू से जानलेवा हमला

जबलपुर, (एजेंसी)। भेड़ाघाट थाना अतंर्गत अंजनी धाम मंदिर के पास हाईवे रोड पर दुर्गा जी देखकर घर आ रहे दो युवकों पर बाईक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिर्याघायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भेड़ाघाट पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कूड़न मोहल्ला निवासी ३६ वर्षीय ठाकुर सिंह राजपूत गत रात लगभग १० बजे अमित पटेल के साथ अमित की स्कूटी से तथा उसका छोटा भाई राजा राजपूत अपनी मोटर साईकिल से जबलपुर दुर्गाजी देखकर घर वापस आ रहे थे रात लगभग १.२० बजे जैसे ही अंजनी धाम मंदिर के पास हाईवे रोड पार करने पर सामने भेड़ाघाट तरफ से एक मोटर साईकिल में सवार तीन अज्ञात लड़के अमित पटेल की स्कूटी के सामने आये तथा गाली गलौज करते हुए बोले कैसी गाडी चला रहा है, गाली देने से मना करने पर दो अज्ञात लड़कों ने अमित और ठाकुर सिंह पर चाकू से हमला कर घायल कर दिर्या दोनों जान बचाकर भागे और आगे सर्विस रोड पर जाकर अमित पटेल बेहोश होकर गिर गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट पर धारा २९६(इ), १०९(१), ३(५) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

खाते में १ रुपए आए तो रहें सतर्क, साइबर ठग लिंक के जरिए बिछा रहे जाल

भोपाल, (एजेंसी)। साइबर ठगी करने वाले जालसाज अब लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए छोटी रकम का सहारा ले रहे हैं। बैंक खाते में एक रुपए जमा होने का फर्जी मैसेज भेजकर उसके साथ लिंक दिया जा रहा है। मैसेज देखकर रकम की जानकारी जुटाने या लेनदेन की पुष्टि करने के लिए लिंक खोलना भारी पड़ सकता है। इसी तरह बैंक से जुड़ी जानकारी देने के बहाने व्हाट्सऐप पर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की जा रही है। साइबर अपराधियों के इन तरीकों को देखते हुए पुलिस ने अनजान लिंक और फाइलों से सावधान रहने की सलाह दी है।

एक सरकारी बैंक में पदस्थ अकाउंटेंट के मोबाइल पर एक रुपए खाते में जमा होने का मैसेज आया। कार्यालय के काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने तत्काल ध्यान नहीं दिया। लंच के समय मैसेज देखा तो बैंक के सिस्टम से लेनदेन की जानकारी निकाली। जांच में पता चला कि खाते में एक रुपया जमा ही नहीं हुआ था, जबकि मोबाइल पर क्रेडिट का संदेश आया था। मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजा गया था। इससे उन्हें संदेह हुआ कि यह साइबर ठगी का प्रयास हो सकता है। ऐसे मामलों में जालसाज लोगों की उत्सुकता का फायदा उठाकर उन्हें लिंक खोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लिंक के जरिए संदिग्ध वेबसाइट पर ले जाने या नुकसान पहुंचाने वाली फाइल डाउनलोड कराने की कोशिश की जा सकती है।

गूगल पर बैंक का नंबर तलाशना भी पड़ा भारी

भोपाल निवासी राजपाल सिंह ने टीकमगढ़ की एक बैंक शाखा से लोन के लिए आवेदन किया था। करीब एक महीने तक प्रक्रिया आगे नहीं बढऩे पर उन्होंने बैंक से संपर्क करने के लिए गूगल पर नंबर तलाशा। वहां मिले एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर दूसरी ओर से बताया गया कि लोन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्यालय में ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति ने व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजने की बात कही। राजपाल ने लिंक देखा तो वह एपीके फाइल थी। उन्हें संदेह हुआ कि बैंक के काम के लिए इस तरह की फाइल क्यों भेजी जा रही है। उन्होंने उसे खोलने से इनकार कर दिया और बैंक जाकर शिकायत करने की बात कही। बाद में पता चला कि संबंधित मोबाइल नंबर किसी धोखेबाज का था। यह घटना बताती है कि इंटरनेट पर मिले किसी फोन नंबर को बैंक का आधिकारिक नंबर मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। बैंक से जुड़ा काम करने के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या सत्यापित संपर्क माध्यम का ही उपयोग करना चाहिए।

६३४ करोड़ की साइबर ठगी, १३७ करोड़ रुपए होल्ड

भोपाल के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी के करीब ८० प्रतिशत मामलों में ओटीपी और मोबाइल लिंक जैसे माध्यमों की भूमिका सामने आती है। उन्होंने लोगों को अनजान लिंक और संदिग्ध संदेशों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में वर्ष २०२५ के दौरान ६३४ करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। इसमें से १३७ करोड़ रुपए होल्ड कराए जा सके, जबकि शेष ४९७ करोड़ रुपए होल्ड नहीं हो पाए। ठगी की रकम को समय रहते होल्ड कराना पीडितों को नुकसान से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है।

एपीके फाइल से मोबाइल का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश

साइबर अपराधी त्योहारों और कारोबार के व्यस्त मौसम में नए-नए बहानों से लोगों को निशाना बनाते हैं। कभी शादी का निमंत्रण कार्ड, कभी बैंक के काम और कभी किसी भुगतान से जुड़ी जानकारी के नाम पर लिंक भेजा जाता है। कुछ मामलों में लिंक के जरिए एपीके फाइल डाउनलोड कराने की कोशिश होती है। ऐसी संदिग्ध फाइल इंस्टॉल करने और उसे अनावश्यक अनुमतियां देने से मोबाइल की जानकारी, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा जोखिम में पड़ सकते हैं।

कुछ मामलों में जालसाज कॉल फॉरवर्डिंग जैसी सेटिंग में बदलाव कराने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि, केवल किसी लिंक पर क्लिक करने से हर बार मोबाइल हैक हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जोखिम लिंक की प्रकृति, डाउनलोड की गई फाइल और दी गई अनुमतियों पर निर्भर करता है।

पूर्व कर्मचारी वाणिज्यिक कर अपर आयुक्तको कर रहा ब्लैकमेल

२० लाख रुपये या मकान दो, नहीं तो कर देंगे बदनाम

जबलपुर, (एजेंसी)। वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ अपर आयुक्त से २० लाख रुपये या मकान की मांग करने और मांग पूरी नहीं होने पर झूठी शिकायत कर बदनाम करने की धमकी देने के मामले में अपर आयुक्त के घरेलू पूर्व कर्मचारी के खिलाफ बेलबाग थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, ५४ वर्षीय सपन कुमार सोनटके वाणिज्यिक कर विभाग, जबलपुर में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने १३ अक्टूबर को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि वर्ष २००७ में ग्वालियर में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ रहने के दौरान मंजू यादव उनके घर पर घरेलू काम करता था। उस दौरान उसकी सहकर्मियों और व्यापारियों से भी जान-पहचान हुई थी। वर्ष २००९ में स्थानांतरण के बाद करीब १६-१७ वर्षों तक उनका मंजू यादव से कोई संपर्क नहीं रहा।

शिकायत के मुताबिक, २७ जुलाई २०२६ को दोपहर करीब २ से ३ बजे के बीच जब वह घमापुर चौराहे से अपने कार्यालय जा रहे थे, तभी मंजू यादव ने उनके मोबाइल फोन और उनके परिचित रवि के मोबाइल पर फोन किया। आरोप है कि उसने २० लाख रुपये या मकान दिलाने की मांग की। मांग पूरी नहीं करने पर झूठी शिकायत कर बदनाम करने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी लगातार फोन कर उन्हें परेशान कर रहा है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी मंजू यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा ३०८(२) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा ३(२)(व्ही) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

शराब पीने के लिए ५०० रुपये मांगे, चाकू से हमला

जबलपुर, (ईएमएस)। गोरखपुर थाना पुलिस के मुताबिक, सेठीनगर निवासी १९ वर्षीय आदर्श बर्मन कक्षा १२वीं का छात्र है। १२ अक्टूबर की रात करीब ९ बजे वह अपने दोस्त रोहित बेन के साथ पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहा था। हाथीताल स्थित सनातन धर्म स्कूल के पास जेब से रुपये गिरने पर दोनों उन्हें तलाश रहे थे। तभी गज्जी ठाकुर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और आदर्श से शराब पीने के लिए ५०० रुपये मांगने लगा। रुपये देने से इनकार करने पर गज्जी ने चाकू से हमला कर आदर्श की जांघ में चोट पहुंचा दी। दोस्त रोहित ने बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

२७ प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सपा का आज प्रदर्शन

जिलों में ज्ञापन देकर कार्यकर्ता ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग करेंगे

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल में २७ प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के समर्थन में समाजवादी पार्टी गुरुवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता ज्ञापन देकर ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भाजपा पर पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ों के समर्थन से सत्ता में आती है, लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं देती। मध्यप्रदेश में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के बाद अब डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब भी लंबित है।

डॉ. यादव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और डॉ. मोहन यादव ने ओबीसी को २७ प्रतिशत आरक्षण दिलाने के बड़े-बड़े वादे किए थे। यहां तक कहा गया था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं रोक सकता, लेकिन जमीनी स्तर पर पिछड़ा वर्ग को उसका हक नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा घोषणाएं करती है, लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल पर पीछे हट जाती है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने डॉ. राममनोहर लोहिया के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी ५२ प्रतिशत से अधिक है, इसलिए आरक्षण भी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्ण वर्ग को १० प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय में विश्वास करता है और अपने अधिकारों की मांग कर रहा है।

नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

डॉ. यादव ने मांग की कि मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी २९ लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर ठोस पहल करनी चाहिए।

जबरन वसूली के लिए चाकू से हमला, दो अलग-अलग घटनाओं में युवकों से मांगे रुपये

जबलपुर, (ईएमएस)। शहर में जबरन रुपये मांगने और विरोध करने पर मारपीट व चाकू से हमला करने की दो घटनाएं सामने आई हैं। ओमती और गोरखपुर थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओमती थाना पुलिस के अनुसार, बड़ा पत्थर निवासी ३० वर्षीय अजय अहिरवार किराये का ई-रिक्शा चलाता है। १२ अक्टूबर की रात करीब १० बजे वह तीन पत्ती पेट्रोल पंप के पास सवारी बैठाने के लिए रुका था। इसी दौरान एक अन्य ऑटो चालक ने सवारी बैठाने के बदले रुपये मांगते हुए विवाद शुरू कर दिया। अजय द्वारा रुपये देने से मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए चाकू जैसी वस्तु से उसके पेट पर हमला कर दिया और जानसे मारने की धमकी देकर भाग गया।

सपा ने ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने और ५० प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण के लिए जरूरी संवैधानिक व कानूनी कदम उठाने की मांग की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सर्वदलीय बैठक में किए गए वादों को पूरा करने और निजी क्षेत्र में भी ओबीसी के लिए आरक्षण व प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की मांग की है।

सपा ने आंकड़े नहीं देने का लगाया आरोप

पार्टी का आरोप है कि ओबीसी के २७ प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में पर्याप्त और ठोस आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मामला कानूनी अड़चनों में फंसा है। सपा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार दिलानेके लिए सरकारको घोषणाओंसे आगे बढक़र प्रभावी कदम उठाने होंगे।

१४ ट्रेनों को रानी कमलापति से चलाने की मांग

भोपाल जंक्शन पर बढ़ते यात्री दबाव, मेट्रो निर्माण और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने का प्लान

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल जंक्शन पर बढ़ते यात्री दबाव, मेट्रो निर्माण और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए १४ ट्रेनों को रानी कमलापति (आरकेएमपी) स्टेशन से चलाने की मांग उठाई गई है। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि ट्रेनों की शिफ्टिंग से भोपाल जंक्शन पर भीड़ कम होगी और दक्षिण भोपाल के यात्रियों को आधुनिक रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। नवंबर में जबलपुर में होने वाली रेलवे की बैठक में यह मुद्दा फिर उठाया जाएगा। भोपाल जंक्शन पर प्रतिदिन करीब ३० हजार यात्री पहुंचते हैं और यहां से लगभग २३० ट्रेनों का संचालन होता है। दूसरी ओर, रानी कमलापति स्टेशन पर रोजाना १० से १५ हजार यात्री पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधियों के अनुसार, आरकेएमपी की यात्री क्षमता करीब ४० से ५० हजार है। ऐसे में दोनों स्टेशनों के बीच यात्री दबाव का संतुलन बनाने के लिए ट्रेनों का संचालन विभाजित किया जा सकता है।

जंक्शन के आसपास जाम से मिलेगी राहत

भोपाल जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर-१ के सामने करीब नौ फीट चौड़ी सडक़ पर ऑटो और कैब चालकों के जमावड़े से यातायात प्रभावित होता है। मेट्रो निर्माण के चलते भी क्षेत्र में आवागमन की परेशानी बढ़ी है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और पार्किंग की समस्या के कारण ट्रेन पकडऩे के लिए पहुंचने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कुछ ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन पर स्थानांतरित करने से पुराने भोपाल के स्टेशन क्षेत्र में यातायात का दबाव घटाया जा सकता है। वहीं, दक्षिण भोपाल के यात्रियों को अपने नजदीकी स्टेशन से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

बीना की ओर जाने वाली १४ ट्रेनों पर विचार

भोपाल जंक्शन से बीना की दिशा में जाने वाली जिन ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन से चलाने की मांग की गई है, उनमें भोपाल-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस, भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल-जबलपुर इंटरसिटी, राज्यरानी एक्सप्रेस, विंध्याचल एक्सप्रेस, भोपाल-चोपन साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस, ऊर्जा राजधानी एक्सप्रेस, भोपाल-लखनऊ गरीब रथ, भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर इंटरसिटी, भोपाल-जयपुर एक्सप्रेस, भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस और भोपाल-बीना मेमू शामिल हैं। यह फिलहाल जनप्रतिनिधियों की मांग है। इन ट्रेनोंको रानी कमलापति स्टेशन से चलाने के संबंधमें रेलवे की आधिकारिक मंजूरी या अंतिम निर्णयकी पुष्टि नहीं हुई है।

दोनों स्टेशनों के बीच छह किलोमीटर की दूरी

भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन के बीच करीब छह किलोमीटर की दूरी है। ट्रेनों का संचालन दोनों स्टेशनों में बांटने से यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार स्टेशन चुनने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, ट्रेन के शुरुआती स्टेशन में बदलाव होने पर यात्रियों को नई व्यवस्था के अनुरूप यात्रा की योजना बनानी होगी। जनप्रतिनिधि नवंबर में जबलपुर में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अब रेलवे के निर्णय पर नजर रहेगी कि यात्री दबाव कम करने और दोनों स्टेशनों की क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए ट्रेनों के संचालन में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।

जालसाजी में बंटी-बब्ली का भी उस्ताद निकला यह मास्टरमाइंड कपल

शातिर मियां-बीवी ने बेटियों के नाम दान की गई ज़मीन पर लिया २ करोड़ का लोन, फिर वसूली रोकने के लिए बेटियों से खुद पर ही करवाए मुकदमे

भोपाल, (एजेंसी)। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ऐसे ठग दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने पहले तो बेटियों के नाम पहले ही दान की जा चुकी ज़मीन को बैंक में गिरवी रखकर २ करोड़ का लोन लिया और बाद में बैंक की वसूली रोकने के लिए बेटियों से ही अपने खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए कि ज़मीन तो बेटियों की है। जॉच के बाद ईओडब्ल्यू ने जालसाज जोड़े बिल्डर जीशान अली और उसकी पत्नी नाजनीन अली के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

दंपती की शुरू से ही थी जालसाजी की प्लानिंग

विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू को की गई शिकायत में आरोप था, कि जीशान अली उनकी पत्नी नाजनीन अली और माँ स्व. निकहत शमीम ने शुरू से ही धोखाधड़ी की नियत से ग्राम बावड़ियाकलां, तहसील हुजूर में स्थित ५२६.८३ वर्गमीटर व्यावसायिक ज़मीन बैंक में गिरवी रखी। आरोप यह भी था कि बेटियों के नाम पहले किया गया हिबानामा बैंक से छिपाया गया और २ करोड़ का लोन लेकर वापस नहीं किया गया। जब बैंक ने वसूली का प्रयास किये तब वसूली रोकने के लिए परिवार के लोगों से अपने ही खिलाफ सिविल मुकदमे दायर करवाए गए। एंजेसी ने पंजाब नेशनल बैंक, उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण जबलपुर और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण इलाहाबाद के रिकॉर्ड लेकर इसकी जाँच की।

पहले जमीन खरीदी फिर तीन बेटियो के नाम किया हिबानामा

जाँच में सामने आया की गिरवी रखी ज़मीन शादाब गृह निर्माण सहकारी समिति की थी। समिति ने ९ अप्रैल २००७ को टेंडर निकाला, जिसमें केवल जीशान अली ने बोली लगाई और ५ फरवरी २००८ को इस ज़मीन की रजिस्ट्री से उनके नाम हो गई। बाद में १० जुलाई २०१३ को यही ज़मीन हिबानामे से उसने अपनी तीन बेटियों के नाम कर दी थी, जिनमें से दो उस समय नाबालिग थीं। यानी २०१३ के बाद यह ज़मीन जीशान अली की नहीं बल्कि उनकी बेटियों की हो चुकी थी। यह बात खुद जीशान अली ने २० फरवरी २०१८ को बैंक के चीफ मैनेजर को लिखे अपने पत्र में मानी है।

२०१५ मे जमीन को अपना दिखाकर ले लिया लोन

इसके बाद २०१५ में बैंक के सामने इस ज़मीन को जीशान अली की अपनी संपत्ति दिखाते हुए बैंक की २२ सितंबर २०१५ की लीगल सर्च रिर्पोट में ज़मीन को साफ़ और बिकने योग्य बताया। साथ ही नाबालिग के हित वाले कॉलम में नॉन लिखा गया। हिबानामे का कहीं ज़िक्र नहीं था। इसी आधार पर २४ सितंबर २०१५को रॉयल हेरिटेज बिल्डर्स के नाम २ करोड़ की ओवरड्रॉफ्ट सीमा स्वीकृत हुई।

परिवार वाले ही बने गारंटर, बताया जमीन्पर कोई दावा नहीं

उसी दिन हुए ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑ गॉरंटी में जीशान अली, नाजनीन अली और स्व. निकहत शमीम गारंटर बने और इसी ज़मीन को गिरवी के लिए दर्शाया गया। एग्रीमेंट में यह घोषणा भी की गई कि संपत्ति पर कोई मुकदमा, भार या दूसरा दावा नहीं है। ४ नंवबर से ६ नंवबर २०१५ के बीच इस ज़मीन का बंधक विलेख रजिस्टर्ड कराया गया। फरवरी २०१५ में जीशान अली और नाजनीन अली ने अपनी नाबालिग बेटी के नाम का एक दूसरा प्लॉट बेचने के लिए जिला न्यायालय से बाकायदा अनुमति ली थी। यानी उन्हें पता था कि नाबालिग की संपत्ति अदालत की अनुमति के बिना नहीं बेची जा सकती। फिर भी छह महीने बाद बेटियों के नाम हिबा की जा चुकी ज़मीन बिना किसी अनुमति और बिना बताए बैंक में गिरवी रख दी गई।

मप्र में आईएएस अफसरों के तबादले: कई जिलों के कलेक्टर बदले

सीनियर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी की गई। इस सूची में कई अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। आदेश के तहत कई जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है, वहीं कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में पन्ना, मऊगंज, नर्मदापुरम, जबलपुर, भिंड, रायसेन, सिंगरौली, बालाघाट, शाजापुर, बुरहानपुर और हरदा समेत कई जिलों में अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है।

इन जिलों में बदले गए कलेक्टर

जबलपुर: रायसेन के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, जबलपुर के पूर्व कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त (मंडी) नियुक्त किया गया है।

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के प्रबंध संचालक आशीष वशिष्ठ को नर्मदापुरम का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, निवर्तमान कलेक्टर सोमेश मिश्रा को एड्स नियंत्रण सोसाइटी और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का संचालक नियुक्त किया गया है।

सिंगरौली: सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल के संचालक अंकित अस्थाना को सिंगरौली का नया कलेक्टर बनाया गया है। सिंगरौली के पूर्व कलेक्टर गौरव बैनल को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल का संचालक बनाया गया है।

रायसेन: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उप सचिव रोहित सिसोनिया को रायसेन जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बुरहानपुर और पन्ना: बुरहानपुर के कलेक्टर हर्ष सिंह को पन्ना जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, पन्ना की निवर्तमान कलेक्टर उषा परमार को मंत्रालय में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अपर सचिव पदस्थ किया गया है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग में उप सचिव विवेक कुमार को बुरहानपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

शाजापुर और हरदा: इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को शाजापुर का कलेक्टर बनाया गया है। शाजापुर की कलेक्टर ऋजु बाफना को उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम को हरदा जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है।

बालाघाट: बालाघाट जिले में आदित्य सिंह को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

भिंड और मऊगंज: वाणिज्यिक कर विभाग के पूर्व अपर सचिव राजेश कुमार ओगरे को मऊगंज का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, सहकारिता विभाग में उप सचिव रहे पवन कुमार जैन को भिंड जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

सीनियर अफसरों को मिले अतिरिक्त प्रभार

रश्मि अरुण शमी (अपर मुख्य सचिव): लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाली रश्मि अरुण शमी को खाद्य सुरक्षा आयुक्त, विशेष आयुक्त (समन्वय) और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

सुखवीर सिंह: मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के दायित्व के साथ-साथ सुखवीर सिंह लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

के.सी. गुप्ता (कृषि उत्पादन आयुक्त): के.सी. गुप्ता को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

भरत यादव: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

संकेत एस. भोंडवे: नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत एस. भोंडवे को आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन (नई दिल्ली) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में कलेक्टरों की नई पदस्थापना के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है।

ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में भाजपा लड़ेगी कानूनी लड़ाई

सरकार ने झाड़ा पल्ला

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में २७ प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की दिशा में बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर प्रदेश की भाजपा सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सरकार की ओर से सीधे कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय भाजपा संगठन के स्तर पर मामला उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। समाचार के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा के बाद यह राय बनी है. आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की ओर से पैरवी की जाएगी। इस दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में आरक्षण से संबंधित कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका बड़ा असर होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा की रणनीति है. कांग्रेस को इसका लाभ न मिले.

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इसके लिए लीव टू अपील का रास्ता अपनाने पर विचार किया जा रहा है। याचिका दाखिल करने को लेकर अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है। २७ प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लंबे समय से प्रदेश की राजनीति और कानूनी प्रक्रिया का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। अब सवाल यह है कि आरक्षण के अधिकार को लेकर राजनीतिक दलों की यह लड़ाई पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने में कितनी प्रभावी साबित होगी।

कंपनी कैंप से ४०० मीटर बिजली केबल चोरी

जबलपुर, (ईएमएस)। बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम परतला स्थित वीआरएस कंपनी के कैंप परिसर से करीब ४०० मीटर बिजली की केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। कंपनी में एचआर पद पर कार्यरत नवीन सिंह राजावत ने पुलिस को बताया कि २६ सितंबर को विद्युत मोटर खराब होने पर सुधार कार्य के लिए गौरी नामक मिस्त्री को बुलाया गया था। बोरवेल से मोटर निकालने के दौरान उससे जुड़ी करीब ४०० मीटर केबल बाहर निकली थी, जिसे म